



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1174) पटना, मंगलवार, 1 जुलाई 2025

सं० ग्रा0वि0-7(नि0)- 01/2025-4254729

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

25 जून 2025

विषय :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति के प्रत्यायोजन के संबंध में ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अंतर्गत वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं (मनरेगा) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक इच्छुक परिवारों के वयस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के अकुशल श्रम की वैधानिक गारंटी देना तथा स्थायी, गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है ।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभागीय निर्गत दिशा-निर्देश के अधीन जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर कार्यान्वित कराये जा रहे मनरेगा योजनाओं से संबंधित प्राक्कलन पर प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार के दिशा-निर्देश (सितम्बर 2006) की कड़िका-9.2 के प्रावधान एवं विभागीय पत्रांक-12686 दिनांक 15.11.2006 एवं पत्रांक-3044 दिनांक 13.03.2008 तथा संकल्प संख्या-9888 दिनांक 25.08.2010 द्वारा संशोधित कर प्रत्यायोजित की गयी थी।

3. विगत वर्षों में मनरेगा योजनाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इस निमित्त योजनागत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में अद्यतन प्रत्यायोजित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा को संशोधित कर समुचित वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्रीय स्तरों पर योजनाओं का ससमय क्रियान्वयन एवं सुसम्पादन सुनिश्चित हो सके।

4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सामग्रियों एवं श्रम घटकों की दरों में उत्तरोत्तर पर्याप्त वृद्धि के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं की प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु पूर्व से प्रदत्त सक्षमता में वृद्धि कर अब निम्नरूपेण क्षेत्रीय पदाधिकारियों/बिहार रूरल

डेवलपमेंट सोसाईटी के पदाधिकारियों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारियों को उनके पदनाम के विरुद्ध उल्लिखित राशि की सीमा के अधीन प्रशासनिक/ तकनीकी स्वीकृति के प्रत्यायोजन हेतु राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 24.06.2025 को मद संख्या-31 में स्वीकृति प्रदान की गई है -

प्रशासनिक / तकनीकी स्वीकृति की प्रत्यायोजित शक्ति

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम | शक्ति का स्वरूप | वर्तमान राशि की सीमा | संशोधित राशि की सीमा |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 1. | प्रधान सचिव/सचिव | प्रशासनिक | तीस करोड़ रुपये से अधिक | यथावत |
| 2. | प्रमंडलीय आयुक्त | प्रशासनिक | तीस करोड़ रुपये तक | यथावत |
| 3. | जिला पदाधिकारी | प्रशासनिक | बीस करोड़ रुपये तक | यथावत |
| 4. | उप विकास आयुक्त | प्रशासनिक | एक करोड़ रुपये तक | यथावत |
| 5. | कार्यक्रम पदाधिकारी | प्रशासनिक | दस लाख रुपये तक | पन्द्रह लाख रुपये तक |
| 6. | ग्राम पंचायत | प्रशासनिक | पाँच लाख रुपये तक | दस लाख रुपये तक |
| 7. | मुख्य अभियंता | तकनीकी | असीमित | यथावत |
| 8. | अधीक्षण अभियंता | तकनीकी | बीस करोड़ रुपये तक | यथावत |
| 9. | कार्यपालक अभियंता | तकनीकी | एक करोड़ रुपये तक | यथावत |
| 10. | सहायक अभियंता | तकनीकी | दस लाख रुपये तक | पन्द्रह लाख रुपये तक |

ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं की स्वीकृति के मामले में 05 (पाँच) लाख रुपये तक की योजनाओं के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प संख्या 9888 दिनांक 05.08.2010 के अनुरूप पूर्व की भांति तकनीकी स्वीकृति हेतु पंचायत द्वारा किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सरकारी कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता की सेवा प्राप्त की जा सकती है। पाँच लाख से अधिक की योजनाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत चालू सभी योजनाओं की मापी के लिए सरकार अथवा बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता सक्षम होंगे, लेकिन योजनाओं की अंतिम मापी एवं अंतिम विपत्र उसी स्तर के कार्यरत तकनीकी पदाधिकारी द्वारा पारित किया जायेगा जो संबंधित योजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु निर्धारित सक्षम पदाधिकारी/प्राधिकार के अन्वय हों।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
लोकेश कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1174-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>